बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 223 ● नई दिल्ली ● सोमवार 22 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नीट परीक्षार्थियों की सुविधा को दी प्राथमिकता, एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक रुके रहे पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को कोलकाता से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने के बाद अपने आवास की ओर प्रस्थान को कुछ समय के लिए टाल दिया ताकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पुनर्परीक्षा देने वाले किसी भी अभ्यर्थी को यातायात पाबंदियों के कारण असुविधा नहीं हो। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री अपराह्न करीब 1:15 बजे हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन वहां से तुरंत लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास रवाना होने के बजाय वहीं रुके रहे। सूत्रों के अनुसार, चूंकि नीट परीक्षा अपराह्न दो बजे शुरू होनी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने परीक्षा शुरू होने के बाद ही आवास के लिए निकलने का निर्णय लिया, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी ना हो और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित ना हो।

दिल्ली सरकार के 200 ग्रेड-1 अधिकारियों को मिला सीनियर स्केल प्रमोशन, 25 साल का इंतजार हुआ खत्म

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रेड-एक के योग्य 200 अधिकारियों को सीनियर स्केल (ग्रुप ए) के पद पर पदोन्नति (प्रमोशन) देने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह निर्णय उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (डीपीसी) की सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। आदेश के मुताबिक यह पदोन्नति पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित कुछ अदालती मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

यदि भविष्य में कोर्ट का फैसला इन अधिकारियों के खिलाफ आता है, तो उन्हें वापस उनके पुराने पद पर भेजा जा सकता है।

जमा करना होगा वचन पत्र

सेवा विभाग ने आदेश में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारियों को एक वचन पत्र भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में अधिकारियों को यह लिखकर देना होगा कि वे कोर्ट के अंतिम नियमों और शर्तों को पूरी तरह से मानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विभाग ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी संबंधित अधिकारियों को हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग फॉर्म आगामी दो कार्य दिवसों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सर्विसेज विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। इनमें से कुछ अधिकारियों को 25 साल तक एक ही स्केल पर अटके रहने के बाद पदोन्नति मिली है।

दिल्ली-एनसीआर में दिखा योग का उत्साह, लोगों ने अपनाया स्वस्थ जीवन का संकल्प

नई दिल्ली । देश-दुनिया के साथ-साथ दिल्ली में भी तमाम लोग और शासन-प्रशासन से जुड़े लोग योग कर रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया। उपराज्यपाल के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन, डीडीए के उपाध्यक्ष डॉ एन सरवन कुमार, हजारों आम लोग योग कर रहे हैं। इसी के साथ सभी ने प्रधानमंत्री मोदीका संबोधन सुना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को पूरी दिल्ली योगमय होगी। राजधानी में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत 29 प्रमुख स्थानों पर मेगा योग इवेंट होंगे, जबकि 730 से अधिक पार्कों को आम लोगों के लिए योग अभ्यास के लिए खुला रखा जाएगा। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू यमुना स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी की नीली झील के किनारे योग करेंगी। डीडीए की ओर से राजधानी के 18 स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और 11 बड़े पार्कों में विशेष योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। द्वारका, साकेत, सीरी फोर्ट, वसंत कुंज और रोहिणी जैसे प्रमुख खेल परिसरों के

साथ स्वर्ण जयंती पार्क, हौज खास पार्क, संजय झील और विजय मंडल पार्क में भी लोगों के लिए योग कार्यक्रम होंगे। प्रवेश को आसान रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भाग ले सकें।

हर विधानसभा क्षेत्र में योग का आयोजन

दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों के पार्कों और खेल मैदानों में योग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और वैश्विक नेतृत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के सैकड़ों देशों में लोग योग के माध्यम से भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ रहे हैं।

गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

गाजियाबाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गाजियाबाद जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन कविनगर स्थित जैनमती उजागरमल जैन इंटर कॉलेज में हुआ।

इसमें स्थानीय निवासियों और योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलकर विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 47वीं वाहिनी पीएसी में जवान योग करते नजर आए। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित लोहिया पार्क में भारत स्वाभिमान योग ट्रस्ट के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने योग किया। डासना स्थित आईएमएस यूसी कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों में उत्साह दिखा और कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर मंत्री सुनील शर्मा व अन्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुरादनगर में आयुध निर्माणी फैक्ट्री स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्व योग दिवस पर योग करते कार्यकारी निदेशक कमलेश कुमार और अन्य लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असोला भाटी स्थित ब्लू लेक के किनारे सैकड़ों योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया।

इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रही, जिसका उद्देश्य स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक करतार सिंह तंवर सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

शाहदरा रेलवे स्टेशन पर पंकज धामा की हत्या पर एक्शन, मुजफ्फरनगर से 8 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो के गार्ड पंकज धामा को पीट-पीटकर हत्या के मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. बागपत के खेकड़ा निवासी पंकज की शनिवार (20 जून) सुबह मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक पंकज धामा पिछले 13 वर्षों से दिल्ली मेट्रो में नौकरी कर रहे थे. शुक्रवार रात उनकी ड्यूटी थी और शनिवार सुबह करीब 6 बजे वह योगा एक्सप्रेस ट्रेन से अपने घर खेकड़ा लौट रहे थे. जैसे ही ट्रेन शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची और पंकज उतरने लगे, तभी कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि युवकों ने पंकज पर लात-घूंसों की बरसात कर दी और उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल पंकज धामा को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन में सवार होकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे. जीआरपी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद पंकज के परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पंकज के पिता राजेंद्र सिंह धामा का कहना है कि अगर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी समय रहते हस्तक्षेप करते तो उनके बेटे की जान बच सकती थी. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है. पंकज धामा अपने परिवार के मुख्य सहारा थे. उनके पीछे दो छोटे बच्चे, बुजुर्ग माता-पिता और पत्नी हैं. परिजनों का कहना है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा न हो. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

अयोध्या मामले में केजरीवाल का बयान- कहा- केवल 200 करोड़ की नकदी चोरी, कई बड़े नाम शामिल; लेकिन नहीं हुई एफआईआर

नई दिल्ली । अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े गड़बड़ी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले में लगातार नए दावे और आरोप सामने आने के बीच विपक्ष ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपये की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि केवल नकदी के रूप में ही करीब 200 करोड़ रुपये चोरी होने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद अब तक न तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस, ईडी या सीबीआई किसे ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र और राय, दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हैं। यदि निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर इस मामले में कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है।

वोट देने के अधिकार को मिले मौलिक अधिकार का दर्जा: कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की जोरदार वकालत करते हुए रविवार को कहा कि यह कदम मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) के तहत विभिन्न रायों में अत्यधिक संख्या में मतदाताओं के नाम हटाये जाने या उन्हें जानबूझकर अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने में एक सशक्त कदम होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे निर्वाचन आयोग के घोर पक्षपातपूर्ण कामकाज के पूरी तरह उजागर होने के बाद, अब समय आ गया है कि मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे इसे उच्चतम स्तर की न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा मिल सकेगी। रमेश ने उल्लेख किया कि बीते शुक्रवार को ही उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के तहत फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। इक्कीस-22 अप्रैल 1947 को हुई इसकी बैठक में मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने पर तीखी बहस हुई थी, जिसमें डॉ. भीमराव आंबेडकर और बाबू जगजीवन राम ने इसके पक्ष में पुरजोर दलीलें दी थीं।

रमेश ने कहा कि सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी और कुछ अन्य नेताओं का मानना था कि यदि मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने में झिझक सकती हैं, और संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करना ही काफी है। उन्होंने कहा, सरदार पटेल ने खुद यह रुख अपनाया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपने आप में एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। यही अनुच्छेद 326 की पृष्ठभूमि है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का

प्रावधान करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले सात दशकों से इस बात पर लगातार बहस चल रही है कि मतदान का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा प्रदान किया गया एक वैधानिक अधिकार है या यह एक स्पष्ट मौलिक अधिकार है। रमेश ने रेखांकित किया, विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं। मार्च 2023 के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के फैसले में (शीर्ष अदालत की पीठ में शामिल) न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने अपनी असहमति की राय में माना था कि मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने खुद यह स्वीकार किया है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, उनके वित्तीय हितों और राजनीतिक चंदा के स्रोतों को जानने का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। रमेश ने तर्क दिया, इसने (शीर्ष अदालत ने) मत की गोपनीयता की रक्षा की है और नोटा (इन विकल्पों में से कोई नहीं) के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के अधिकार को मान्यता दी है। इसलिए, यह और भी अधिक असंगत है कि मतदान का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार बना हुआ है। इससे मिलते जुलते सभी अधिकारों को मौलिक घोषित कर दिया गया है, लेकिन वैसा मूल अधिकार जिसके बिना पहले वाले (अधिकार) अस्तित्व में नहीं रह सकते, वह अब भी वैधानिक (अधिकार बना) है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे भारत के निर्वाचन आयोग के घोर पक्षपातपूर्ण कामकाज के पूरी तरह उजागर होने के बाद, अब समय आ गया है कि मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। इससे इसे उच्चतम स्तर की न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा मिल सकेगी। रमेश ने कहा, यह कदम एसआईआर प्रक्रिया के तहत विभिन्न रायों में अत्यधिक संख्या में मतदाताओं के नाम हटाये जाने या उन्हें जानबूझकर अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने में एक शक्तिशाली कदम होगा। इसका यह भी अर्थ होगा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज पर शीर्ष अदालत की अधिक निगरानी रहेगी। शीर्ष अदालत ने जब शुक्रवार को फैसला सुनाया कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो रमेश ने कहा था कि मतदान के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार घोषित करने के बारे में क्या राय है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र को उसकी मौजूदा विनाशकारी स्थिति से बचाने के लिए यह सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि सीमांकित मार्गों पर फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मोटर वाहनों पर प्राथमिकता मिलेगी और यह अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत गारंटीकृत आवागमन के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदूरकर की पीठ ने माना कि किसी नागरिक का सीमांकित फुटपाथ पर चलने का अधिकार प्राथमिक है और इसे मोटर वाहनों के आवागमन पर प्राथमिकता दी जाएगी।

सम्पादकीय...

योग

21 जून 2026 को भारत सहित पूरी दुनिया ने 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और भव्यता के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से देश और दुनिया को संबोधित करते हुए योग के महत्व को रेखांकित किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास कर इस अभियान को नई ऊर्जा प्रदान की। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग अर्थात स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई, जो जीवन के हर चरण में योग की उपयोगिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21 जून पृथ्वी का सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन अब यह दिन दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक उत्सव के रूप में भी स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा की अभिव्यक्ति है। योग लोगों को जोड़ने का माध्यम है और यह किसी विशेष आयु, धर्म, वर्ग या देश तक सीमित नहीं है। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो मानवता को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश देता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत की पहल पर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके बाद से हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आज यह आयोजन 190 से अधिक देशों में लाखों लोगों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाता है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग 30 हजार लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। पश्चिम बंगाल में पहली बार योग दिवस को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, छात्रों, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भाग लिया। विशाल संख्या में लोगों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि योग अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बन चुका है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी इस अवसर को विशेष बनाने के लिए देशभर के 100 प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए। इन आयोजनों का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर और योग परंपरा को एक साथ प्रस्तुत करना था। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। 210 से अधिक भारतीय मिशनों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की, जिससे योग की वैश्विक स्वीकार्यता और लोकप्रियता का परिचय मिला। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने योग दिवस से पहले रन फॉर योगा और विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उनका मानना है कि नियमित योगाभ्यास से मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवनशैली संबंधी रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झांसी में योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए लोगों से नियमित योग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन, मस्तिष्क और आत्मा भी स्वस्थ रहेंगे। योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है तथा रोगों से दूर रखता है। वर्तमान समय में जब दुनिया तनाव, अवसाद, अनियमित जीवनशैली और अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही है, तब योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक शोध भी यह सिद्ध कर चुके हैं कि योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। योग तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, नींद में सुधार लाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम विशेष रूप से वृद्धावस्था में स्वास्थ्य और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में आने वाले बदलावों और बीमारियों से निपटने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियमित योगाभ्यास से बुजुर्गों की शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यही कारण है कि इस वर्ष की थीम को दुनिया भर में व्यापक समर्थन मिला। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि योग भारत की प्राचीन विरासत होने के साथ-साथ आधुनिक विश्व की आवश्यकता भी है। यह केवल व्यायाम की पद्धति नहीं, बल्कि संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की कला है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, योग मानवता को जोड़ने वाला माध्यम है। आज जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य और मानसिक शांति की तलाश में है, तब योग एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करता है जो व्यक्ति, समाज और विश्व को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। योग दिवस का यह आयोजन न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह दुनिया को स्वास्थ्य, सद्भाव और एकता का संदेश देने वाला एक वैश्विक उत्सव भी बन चुका है। योग की यही सार्वभौमिक भावना इसे 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली जन-आंदोलनों में से एक बनाती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय तेल टैंकरों की सुरक्षित वापसी

भारत के लिए 21 जून 2026 का दिन ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हुआ। तीन भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर–देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड–सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर भारत की ओर रवाना हो गए। इन जहाजों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल और 94 भारतीय नाविक सवार हैं। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, यह घटनाक्रम भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि तीनों जहाज सुरक्षित रूप से जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं और अपने निर्धारित भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश वैभव 24 जून को गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पहुंचेगा। इस जहाज में लगभग 2.86 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल और 37 भारतीय नाविक सवार हैं। वहीं देश विभोर 2.88 लाख मीट्रिक टन तेल और 27 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ गुजरात के ही सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा। तीसरा जहाज सनमार हेराल्ड लगभग 2.85 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर 1 जुलाई को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचेगा। यह सफलता केवल तीन जहाजों की सुरक्षित यात्रा भर नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता का भी प्रतीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से प्राप्त करता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव या व्यापारिक बाधा वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। हाल के महीनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर खतरे की स्थिति पैदा हो गई थी। सुरक्षा चिंताओं के चलते कई वाणिज्यिक जहाजों ने अपनी गतिविधियां सीमित कर दी थीं। एक समय ऐसा भी आया जब लगभग 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास फंस गए थे। समुद्री बीमा की लागत बढ़ गई थी और तेल आपूर्ति में बाधा की आशंकाएं पैदा हो गई थीं। भारत सरकार ने इस दौरान स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय ने समन्वय स्थापित कर भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के समुद्री हितों और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा और ऊर्जा जीवनरेखा की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ समझौता भी है। दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगाया गया नौसैनिक अवरोध हटाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही क्षेत्र में तनाव कम करने और व्यापक वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस कदम का सीधा असर समुद्री व्यापार और तेल परिवहन पर पड़ा है। जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य होने लगी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी इससे सकारात्मक संकेत मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिरता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका असर परिवहन, उद्योग, महंगाई और वैश्विक आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह चुनौती और अधिक गंभीर हो सकती है क्योंकि ऊर्जा आयात पर उनकी निर्भरता अधिक है। भारत पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना इसी रणनीति का हिस्सा है। फिर भी पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख स्रोत बना हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के राष्ट्रीय हितों से सीधे जुड़ी हुई है। तीनों भारतीय टैंकरों की सुरक्षित वापसी यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भारत अपनी समुद्री और ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को सुरक्षित रखने में सक्षम है। यह भारतीय नाविकों के साहस, सरकारी एजेंसियों के समन्वय और भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता का भी प्रमाण है। साथ ही यह संकेत देता है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को नई गति मिल सकती है। अंततः, होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय तेल टैंकरों का सुरक्षित गुजरना केवल एक समुद्री घटना नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विकास है। ऐसे समय में जब विश्व अनेक भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह सफलता भारत के लिए आश्वस्त करने वाली खबर है और भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत भी।

शांति

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का भविष्य 48 घंटों के भीतर ही खतरे में पड़ता दिखाई दिया। इजराइल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमलों से क्रुद्ध ईरान ने स्विट्जरलैंड में होने वाली पहले ही दौर की शांति वार्ता में भाग लेने से इंकार कर दिया और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजराइल और लेबनान में युद्ध विराम लागू हो गया है लेकिन इजराइल ने रातभर लेबनान पर हमले जारी रखे। अमेरिका और ईरान में समझौता शांति और स्थिरता की कठिन राह पर पहला कदम है लेकिन इजराइल इस समझौते को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि सभी पक्षों में भरोसे की कमी है। क्या अमेरिका ने इजराइल को विश्वास में नहीं लिया था? डोनाल्ड ट्रम्प ने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही हस्ताक्षर कर युद्ध से पीछा छुड़ा लिया है। पश्चिम एशिया में अगर शांति की बजाय विध्वंस फिर से शुरू हुआ तो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल न ईरान में सत्ता परिवर्तन करा सके और न ही उसकी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर पाए। अमेरिका ने जिन लक्ष्यों को लेकर युद्ध शुरू किया था, 108 दिन बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब शांति समझौते का लक्ष्य होर्मुज को खुलवाना और अपनी नाकेबंदी हटाना तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करना रह। पराई जंग में खाड़ी देश भी अपने हाथ जलाने को तैयार नहीं है। अमेरिका को स्वयं खरबों का नुकसान हो चुका है। इजराइल की आपत्ति के बावजूद ट्रम्प ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाया लेकिन नेतन्याहू समझौते को पलीता लगाने में तुले हुए हैं। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग खोलने पर सहमति जता दी थी और तेल टैंकर निकलने भी शुरू हो गए थे लेकिन इजराइली हमलों ने फिर तनाव पैदा कर दिया। ईरान के इस मार्ग की निगरानी का प्रभार सम्भाल रहे प्राधिकरण ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सभी जहाज संचालकों को अपना पंजीकरण कराने को कहा गया है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि ईरान जहाजों से टोल वसूली की व्यवस्था शुरू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो तेल और गैस परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। अब ट्रम्प नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं और उनका दबाव काम कर रहा है। दावा तो यही किया जा रहा है कि इजराइल अब लेबनान पर हमले नहीं करने को लेकर मान गया है। ट्रम्प नेतन्याहू को इस बात का अहसास दिला रहे हैं कि अमेरिकी समर्थन के बिना इजराइल कुछ भी नहीं। यह बात काफी हद तक सही भी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति समझौते की आलोचना कर रहे हैं। इजराइली कैबिनेट मंत्रियों को फटकार भी लगाई है। वेंस ने तो यहां तक कह डाला कि? इजराइल को दिए गए हथियारों में से दो-तिहाई अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से बनाए और फंड किए गए हैं। अमेरिका की गलती यही थी कि उन्होंने (इजराइल की तरह) यह मान लिया था कि ईरानी परमाणु मुद्दे का सैन्य समाधान संभव है। वाशिंगटन ने ईरान के संकल्प, रणनीतिक गहराई और भौगोलिक लाभों को कम करके आंका। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा था, -गुरिल्ला तभी जीतता है जब वह हारता नहीं है-। ईरान ने यह युद्ध न हारकर जीता, जबकि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के कारण हार गया। परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने वाली है, ऐसे में श्री ट्रम्प आज उस स्थिति से कमजोर हैं जो बराक ओबामा की 2013-15 में ईरान के साथ वार्ता के दौरान थी।

क्या कीर स्टारमर का युग समाप्ति की ओर? ब्रिटेन में बढ़ते नेतृत्व संकट की कहानी

> विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, ब्रिटेन में राजनीतिक अनिश्चितता का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कीर स्टारमर अपने पद पर बने रहेंगे या लेबर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता चुनेगी। आने वाले कुछ दिन ब्रिटिश राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो यह केवल एक राजनीतिक अध्याय का अंत नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन के लिए एक नए नेतृत्व संघर्ष की शुरुआत भी होगी। अंततः, यह पूरा घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जनता और अपनी पार्टी का भरोसा बनाए रखना भी है।

ब्रिटेन की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 के आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अब अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार स्टारमर सोमवार को अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं या फिर अपने प्रस्थान की समयसीमा तय कर सकते हैं। हालांकि सरकार के सूत्रों ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अभी भी शासन चलाने पर पूरी तरह केंद्रित हैं। यदि यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह केवल एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन की राजनीति में पिछले एक दशक से जारी अस्थिरता का एक और अध्याय होगा। पिछले दस वर्षों में ब्रिटेन ने पहले ही कई प्रधानमंत्रियों का बदलाव देखा है। ऐसे में स्टारमर का संभावित प्रस्थान यह संकेत देता है कि देश की राजनीति अभी भी स्थिर नेतृत्व की तलाश में है। कीर स्टारमर ने 2024 में लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिलाकर सत्ता में वापसी कराई थी। उस समय उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा था जो वर्षों से चली आ रही राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, आर्थिक विकास और जीवन स्तर बेहतर बनाने का वादा किया था। लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार कई विवादों, नीतिगत यू-टर्न और प्रशासनिक चुनौतियों में घिर गई। इन घटनाओं ने उनकी लोकप्रियता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हाल के महीनों में जनमत सर्वेक्षणों में उनकी स्वीकार्यता तेजी से घटी है। आम जनता के बीच यह धारणा बनी है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है। बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, आर्थिक सुस्ती और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पार्टी के भीतर से सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार लेबर पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने सार्वजनिक रूप से स्टारमर से पद छोड़ने या कम से कम अपने प्रस्थान की समयसीमा घोषित करने की मांग की है। यह संख्या पार्टी के कुल सांसदों का लगभग एक चौथाई है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्तारूढ़ दल के इतने बड़े वर्ग का भरोसा अपने नेता से उठ जाए, तो नेतृत्व संकट लगभग अपरिहार्य हो जाता है। बताया जा रहा है कि स्टारमर ने कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, दानदाताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं से बातचीत के बाद अपनी स्थिति पर विचार किया है। हालांकि अभी तक उनके कार्यालय की ओर से इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके विपरीत, स्टारमर ने हाल ही में कहा था कि वह अपने नेतृत्व को चुनौती देने वाले किसी भी प्रयास का मुकाबला करेंगे और पार्टी को आंतरिक संघर्ष से बचने की सलाह दी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अधिक चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है एंडी बर्नहैम। 56 वर्षीय बर्नहैम वर्तमान में ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं और लेबर पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक महत्वपूर्ण संसदीय उपचुनाव में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। बर्नहैम को स्टारमर के सबसे संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थकों का मानना है कि वे पार्टी को नया नेतृत्व और नई दिशा दे सकते हैं। अपनी चुनावी जीत के बाद दिए गए भाषण में उन्होंने देश के लिए नया रास्ता प्रस्तुत करने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से नेतृत्व की चुनौती पेश नहीं की है, लेकिन उनके सहयोगियों ने स्टारमर से स्वेच्छा से पद छोड़ने की अपील की है।

बर्नहैम के अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि नेतृत्व का अवसर आता है तो वे भी दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा अब केवल अटकल नहीं रह गई है, बल्कि एक वास्तविक राजनीतिक संभावना बन चुकी है।ब्रिटेन की राजनीति में यह संकट केवल व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है। इसके पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। पिछले एक दशक में देश ने ब्रेक्सिट, कोविड-19 महामारी, आर्थिक मंदी, बढ़ती जीवन-यापन लागत और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई चुनौतियों का सामना किया है। जनता लगातार ऐसी सरकार की तलाश में है जो स्थिरता और परिणाम दोनों प्रदान कर सके। लेकिन बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से यह लक्ष्य और दूर होता दिखाई देता है। यदि स्टारमर पद छोड़ते हैं या उन्हें हटाया जाता है, तो ब्रिटेन को दस वर्षों से कुछ अधिक समय में सातवां प्रधानमंत्री मिलेगा। यह स्थिति आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में बेहद असामान्य मानी जाएगी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जनता और राजनीतिक दल दोनों ही दीर्घकालिक नेतृत्व मॉडल विकसित करने में संघर्ष कर रहे हैं। इस संकट का असर केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, अमेरिका और अन्य वैश्विक साझेदार ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता पर नजर रख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी यह जानना चाहेंगे कि अगला नेतृत्व आर्थिक नीतियों और विदेश नीति को किस दिशा में ले जाएगा। विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, ब्रिटेन में राजनीतिक अनिश्चितता का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कीर स्टारमर अपने पद पर बने रहेंगे या लेबर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता चुनेगी। आने वाले कुछ दिन ब्रिटिश राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि स्टारमर इस्तीफा देते हैं तो यह केवल एक राजनीतिक अध्याय का अंत नहीं होगा, बल्कि ब्रिटेन के लिए एक नए नेतृत्व संघर्ष की शुरुआत भी होगी। अंततः, यह पूरा घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जनता और अपनी पार्टी का भरोसा बनाए रखना भी है। कीर स्टारमर ने एक समय ब्रिटेन को बदलाव का सपना दिखाया था। अब देखना यह है कि वह उस सपने को बचा पाते हैं या इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसकी बड़ी जीत के बाद बड़ी निराशा आई।

रोगियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी उत्पन्न कर सकते हैं

वैश्विक स्तरपर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 जून 2026 को जनस्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 की धारा 26ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर 16 फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित औषधि नीति का स्पष्ट संकेत भी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया दवा सुरक्षा,एंटीबायोटिक प्रतिरोध, तर्कसंगत औषधि उपयोग और रोगी सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन अर्थात ऐसी दवाएं जिनमें दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक ही दवा के रूप में तैयार किया जाताहै चिकित्सा विज्ञान में एफडीसी का सिद्धांत नया नहीं है। यदि दो या अधिक दवाओं का संयोजन रोगी के लिए अधिक प्रभावी, सुरक्षित, सुविधाजनक और उपचार अनुपालन को बेहतर बनाने वाला हो तो ऐसे संयोजन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्षय रोग, एचआईवी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी अनेक बीमारियों के उपचार में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एफडीसी दवाओं कासफल उपयोग किया जाता हैमैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन क्लिनिकल परीक्षण और चिकित्सीय औचित्य के बिना अनेक दवा संयोजन बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे संयोजन न केवल अपेक्षित लाभ देने में विफल रहते हैं, बल्कि कई बार रोगियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी उत्पन्न कर सकते हैंस्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विशेषज्ञ समितियों, तकनीकी सलाहकार समूहों और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित 16 एफडीसी दवाओं का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य उपलब्ध नहीं है।उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि इन दवाओं के उपयोग से होने वाले संभावित जोखिम इनके संभावित लाभों की तुलना में अधिक हैंइसलिए जनहित और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया। साथियों, इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत में तर्कसंगत औषधि उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। चिकित्सा विज्ञान का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक दवा का उपयोग केवल तभी किया जाए जब उसका लाभ उसके जोखिम से अधिक हो। यदि किसी दवा या दवा संयोजन के प्रभावी और सुरक्षित होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हों, तो उसका बाजार में बने रहना उचित नहीं माना जा सकता। यही सिद्धांत इस निर्णय की आधारशिला हैप्रतिबंधित 16 एफडीसी दवाओं में विभिन्न श्रेणियों के संयोजन शामिल हैं। इनमें एंटीबायोटिक संयोजन, दर्द निवारक दवाएं, त्वचा रोग उपचार संबंधी क्रीम और लोशन, मधुमेह उपचार के कुछ बहु-घटक संयोजन, एंटीफंगल- स्टेरॉयड-एंटीबायोटिक क्रीम तथा अन्य बहु-घटक दवा संयोजन शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित संयोजनों में निम्न प्रकार के प्रमुख संयोजन शामिल हैं-निश्चित खुराक संयोजन दवाओं की प्रतिबंधित सूची एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़ + लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेन्स, एमोक्सिसिलिन + सेराटियोपेप्टिडेज़ एमोक्सिसिलिन + क्लोक्सासिलिन + लैक्टिक एसिड बैसिलस + सेराटियोपेप्टिडेज़,सेफ्यूरोक्सिम + सेराटियोपेप्टिडेज़, सेफ्ट्रिएक्सोन + प्रोबेनेसिड, ड्राइसाइक्लोमाइन + पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड + क्लोर्डियाजेपॉक्साइड,डाइसाइक्लोमाइन +पैरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड,एलोवेरा का अर्क + एलेंटोइन + अल्फाटोकोफेरोल एसीटेट + डी-पैन्थेनॉल + विटामिन ए,एलोवेरा का अर्क + विटामिन ई + ट्राइमेथिकोन + ग्लिसरीन, एलोवेरा + जोजोबा ऑयल + विटामिन ई,एलोवेरा + संतरे का तेल, एलोवेरा + विटामिन ई + इथेल,पैरासिटामोल + लिग्नोकेन ग्लिक्लाजाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट समिति द्वारा समीक्षा की गई दो अतिरिक्त निश्चित खुराक वाली दवाओं के संयोजन को भी पर्याप्त चिकित्सीय समर्थन के अभाव में प्रतिबंधित कर दिया गया।

अन्य वैज्ञानिक आधारहीन बहु-घटक एफडीसी उत्पाद। साथियों, उल्लेखनीय है कि अंतिम आधिकारिक अधिसूचना में प्रत्येक उत्पाद का विस्तृत रासायनिक नाम, शक्ति तथा संरचना का विवरण उपलब्ध होता है, जिसके आधार पर संबंधित उत्पादों की पहचान की जाती हैइन प्रतिबंधित दवाओं में एंटीबायोटिक संयोजनों को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई है।आज पूरी दुनिया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अर्थात एंटीबायोटिक प्रतिरोध की गंभीर समस्या से जूझ रही है। जब एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक या अनुचित उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु धीरे-धीरे उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप सामान्य संक्रमणों का उपचार कठिन हो जाता है और मृत्यु दर बढ़ने लगती है। विश्व स्वास्थ्य समुदाय कई वर्षों से चेतावनी दे रहा है कि यदि एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में सामान्य संक्रमण भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक आधार के बिना तैयार किए गए एंटीबायोटिक संयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सटीकता से गंभीर खतरा बन सकते हैं।

साथियों, भारत विश्व के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा अनेक विकसित देशों में भारतीय दवाओं का व्यापक उपयोग होता है। इसलिए भारत की औषधि नियामक प्रणाली द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय वैश्विक औषधि बाजार और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी प्रभाव डालता है। जब भारत किसी दवा या दवा संयोजन को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिबंधित करता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि रोगी सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रमाण सर्वोच्च प्राथमिकता हैंइस निर्णय का कानूनी आधार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए है। यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि किसी दवा के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है अथवा उसके सुरक्षित एवं प्रभावी होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हों, तो सरकार उसके निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा सकती हैयह प्रावधान भारतीय औषधि नियामक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को संभावित रूप से हानिकारक दवाओं से बचाना है।भारत सरकार इससे पहले भी कई अवसरों पर इसी धारा का उपयोग कर चुकी है। पिछले वर्षों में सैकड़ों फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन निर्णयों का उद्देश्य भी यही था कि बाजार में केवल वही दवाएं उपलब्ध रहें जिनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो।वर्तमान निर्णय उसी प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैदवा उद्योग के दृष्टिकोण से भी यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।आधुनिक फार्मास्युटिकल उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता नियंत्रण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। जब नियामक संस्थाएं वैज्ञानिक मानकों को कठोरता से लागू करती हैं,तो दवा कंपनियां भी अधिक शोध, बेहतर क्लिनिकल परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रेरित होती हैं। इससे पूरे उद्योग की विश्वसनीयता बढ़ती है और रोगियों को सटीकता से सुरक्षित उपचार उपलब्ध होता है। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि दवा बाजार में केवल उत्पादों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लक्ष्य यह होना चाहिए कि उपलब्ध प्रत्येक दवा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, प्रभावी और सुरक्षित हो। यही कारण है कि विश्व के विकसित देशों में दवाओं की स्वीकृति के लिए कठोर वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक होते हैं। भारत भी इसी दिशा में, आगे बढ़ रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का हो रहा प्रयास - सदर विधायक

पडरौना, कुशीनगर। स्थानीय क्षेत्र के ग्राम जंगल बेलवा मटियरवा दलित बस्ती में प्राथमिक विद्यालय से बरगद टोला जूनियर हाईस्कूल तक पक्की सड़क के निर्माण को विधायक मनीष जायसवाल ने नींव की ईंट रखा। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति तक विकास पहुंचाकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के सपनों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का प्रस्ताव विधायक मनीष जायसवाल ने दिया था जिसकी स्वीकृति मिलते ही ग्रामीणों में खुशी व्याप्त हो गई।

सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित

योग को जीवनशैली अपनाने का दिया संदेश, विद्यार्थियों ने किया योगाभ्यास

भटनी देवरिया।

12वें अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय, भरहेचौरा भटनी परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार सिंह ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्राचार्य डॉ. संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि योग स्वस्थ एवं संतुलित जीवन की आधारशिला है । इस दौरान एनएसएस के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोग जीवन जीने का संकल्प लिया। अंत में राष्ट्रहित एवं जनकल्याण की भावना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भटनी थाने में हुआ सामूहिक योगाभ्यास

योग अपनाकर स्वस्थ जीवनशैली का दिया गया संदेश

भटनी देवरिया। 12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में दिन रविवार को थाना भटनी परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय एवं पुलिस कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया। योग कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को दैनिक जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर स्वस्थ जीवनशैली एवं योग के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पडरौना में सामूहिक योगाभ्यास, 90 वर्षीय ध्रुव नारायण पांडेय सम्मानित

पडरौना, कुशीनगर । अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद पडरौना एवं पतंजलि परिवार के संयुक्त तत्वावधान में जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष ने कहा कि योग व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है तथा स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने सभी को योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं योगगुरु बाबा रामदेव का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रकाश कुमार ने योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी सुभाष सिंह ने आयुष मंत्रालय के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। प्रतिभागियों को सूर्य नमस्कार, आयुर्वेद तथा गिलोय, अश्वगंधा, निर्गुण्डी, एलोवेरा सहित विभिन्न औषधीय पौधों के लाभों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में 90 वर्ष से अधिक आयु के ध्रुव नारायण पांडेय को नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान ईओ संतराम सरोज, योग प्रशिक्षक अरविंद कुमार, मनीष जायसवाल, शत्रुधन शाही, अमरदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में योग साधक एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

नहर में नहाते समय पाइप में फंसा युवक, डूबने से मौत; चार बचों पर टूटा दुखों का पहाड़

नेबुआ नौरंगिया (कुशीनगर)।

थाना क्षेत्र में नेबुआ देसी शराब भट्ठी के सामने स्थित नहर में शनिवार दोपहर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान श्रवण राजभर (35) पुत्र नागेश्वर राजभर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रवण नहर में नहाने के लिए उतरा था, तभी वह नहर में लगे पाइप में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। काफी देर बाद उसका

शव पुल के पास फंसा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सब इंस्पेक्टर मणिन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। काफी प्रयास के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि श्रवण की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। उनके चार बचे हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र सन्नी, पुत्री रविना, तथा अमित और अमर शामिल हैं। पिता की असामयिक मौत के बाद बचों के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में शोक की लहर है।

नीट (यूजी) पुनः परीक्षा-2026- कुशीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न

कुशीनगर। नीट (यूजी) पुनः परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा तथा अधिकारियों ने लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने किसान इंटर कॉलेज साखोपार सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं क्षेत्राधिकारी कसया कुंदन सिंह ने कृषक इंटर कॉलेज मल्लूडीह एवं बुद्धा पीजी कॉलेज, कुशीनगर का भ्रमण कर सुरक्षा एवं परीक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता बरतने तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जनपद में परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

विश्व योग दिवस पर कुबेरस्थान शिव मंदिर में योग शिविर, सैकड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास

कुबेरस्थान (कुशीनगर)। विश्व योग दिवस के अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर, कुबेरस्थान परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग समिति के जिला महासचिव एवं योग प्रशिक्षक डॉ. इंद्रजीत सिंह के मार्गदर्शन तथा राघवेंद्र शर्मा की देखरेख में हुआ। शिविर में विभिन्न गांवों से पहुंचे सैकड़ों योगार्थियों ने ग्रीवा चालन, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, मंडूकासन, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान तथा सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि योग जीवन का आधार है। नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति निरोग एवं स्वस्थ रहता है तथा जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। वहीं अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रभुनाथ गुप्ता ने विश्व योग दिवस की महत्ता एवं योग के लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में योग साधक, स्थानीय नागरिक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बांसी नदी के तट पर गूंजा योग का संदेश, स्वछता और वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

पडरौना,कुशीनगर । लोक आस्था से जुड़ी जनपद की प्रमुख सहायक नदी बांसी के तट पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्साहपूर्वक सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला गंगा समिति कुशीनगर (नमामि गंगे) के तत्वावधान में वन क्षेत्र पड़रौना रेंज स्थित बांसी नदी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में योग के साथ-साथ स्वछता एवं वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। "Yoga for Healthy Ageing" थीम पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। राज्य स्वछ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में प्रातःकाल योगाभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक संतोष त्रिपाठी ने प्रतिभागियों को विभिन्न

योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

क्षेत्रीय वन अधिकारी पड़रौना अशोक कुमार यादव ने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का सबसे सरल माध्यम है। योग और प्रकृति का संबंध अत्यंत गहरा है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को जनआंदोलन बनाना आवश्यक है। जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति कुशीनगर (नमामि गंगे) नम्रता भट्ट ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर नदी घाटों पर कार्यक्रम आयोजित

करने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के साथ-साथ नदी संरक्षण और स्वछता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही स्वछ एवं अविरल नदियों का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। योग प्रशिक्षक आदित्य दुबे ने कहा कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। योग प्रशिक्षक संतोष त्रिपाठी नें कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है तथा जीवन को अधिक संतुलित और स्वस्थ बनाया जा सकता है। योग कार्यक्रम के पूर्व बांसी नदी घाट पर स्वछता अभियान चलाया गया। उपस्थित लोगों ने नदी तट से कूड़ा-कचरा हटाकर स्वछता का संदेश दिया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जिला गंगा समिति (नमामि गंगे) के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम

इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के अंतर्गत पौधे लगाए गए । कार्यक्रम में ग्राम प्रधान (जंगल सिंहपट्टी) बबलू कुशवाहा, डॉ. आदित्य दुबे, क्षेत्रीय वनाधिकारी पड़रौना अशोक कुमार यादव, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट, वन रक्षक आकाश त्रिपाठी, संदीप पटेल, मुन्ना गोंड, लड्डू गोंड, आनंद पांडेय, हंसलोक पांडेय, नमूना गद्दी, निजामुद्दीन अंसारी, परमवीर साहनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मैं सबसे माफी मांगता हूं कि मैंने गद्दारों के लिए वोट मांगे - बागियों पर बरसे उद्धव; संजय राउत का किया बचाव

मुंबई । शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब केवल एक ही शिवसेना है और उसका नेतृत्व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। मुंबई के भांडुप में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरे नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। यह इलाका शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद संजय पाटिल के लोकसभा क्षेत्र मुंबई उत्तर-पूर्व में आता है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात और सांसदों के बिक जाने के बावजूद शिवसैनिक मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। उद्धव ने कहा, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने एक गद्दार के लिए वोट मांगे थे। मैंने सभी लोकसभा सीटों पर प्रचार किया था। मैंने उनको (संजय दीना पाटिल) को टिकट दिया था। चुनाव जीतने के बाद उनका भाव बढ़ गया और फिर उन्होंने खुद को बेच दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं के पार्टी छोड़ने और राजनीतिक फायदे के लिए पक्ष बदलने का चलन

लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, क्या किसी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? एक दिन कांग्रेस का ही कोई नेता भाजपा का अध्यक्ष बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन अब स्थिति भाजपा युक्त कांग्रेस जैसी हो गई है। वहीं, संजय राउत के विवादित बयानों पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि तुम गाली देते हो, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना ने करीब 30 साल तक कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी शिवसेना को तोड़ने या खत्म करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने शिवसेना को कमजोर करने और उसके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया। यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा, हमने 30 साल तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारी पार्टी को चुराने या खत्म करने की कोशिश नहीं की। भाजपा ने वही किया, जो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक समय भाजपा की राजनीतिक ताकत बहुत सीमित थी और महाराष्ट्र में पार्टी को बढ़ने में अविभाजित शिवसेना की बड़ी भूमिका रही है। बता दें कि एक दिन पहले कोल्हापुर में अमित शाह ने कहा था कि पहले एकनाथ शिंदे गुट को अलग पहचान के साथ बताना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है और केवल एक ही शिवसेना है, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा संपन्न, लगभग 22.79 लाख अभ्यर्थी ने दी परीक्षा

नई दिल्ली । देश के 22.79 लाख से ज्यादा छात्रों ने आज नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा दी। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,440 केंद्र बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच हुई। छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक एग्जाम सेंटरों में एंट्री दी गई। एक-दो मिनट देर से पहुंचने पर मुंबई में 2 और बेंगलुरु में 4 स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। बेंगलुरु में लड़कियों ने रेलिंग कूदकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन एग्जाम रूम का गेट बंद हो चुका था। राजस्थान के अजमेर में हिजाब पहन कर आई एक छात्रा को एंट्री देने से पहले मना किया गया। काफी बहस के बाद उसे अंदर भेजा गया। इधर, हैदराबाद में 19 साल की एक नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उसके अपार्टमेंट में फंदे से लटका शव मिला। पुलिस को आशंका है कि उसने री-एग्जाम के दबाव में यह कदम उठाया। मौके से मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया।

नीट री-एग्जाम, एक-दो मिनट देर से पहुंचे छात्रों को नो-एंट्री
हिजाब पर विवाद, कलावा-इयररिंग्स उतरवाए, कपड़ों से मेटल बटन निकाले; हैदराबाद में छात्रा ने सुसाइड किया

2 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात, एयरफोर्स ने पेपर पहुंचाए

एनटीए की यह री-एग्जाम नीट-यूजी की 3 मई की परीक्षा रद्द होने के चलते कराना पड़ा है। 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसकी जांच हो रही है। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया गया। पहली बार वायुसेना के विमान और हेलिकॉप्टरों ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट-यूजी के क्वेश्चन पेपर देश के अलग-अलग जोन तक पहुंचाए। री-एग्जाम के लिए 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। एनटीए के मुताबिक, 95 हजार से ज्यादा एग्जाम सेंटरों में सीसीटीवी से निगरानी हुई। कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए थे।

सीफूड यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से सात महिलाओं की मौत

तिरुवल्लूर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में रविवार को एक सीफूड निर्यात इकाई में अमोनिया गैस रिसाव की घटना सामने आई है। यह रिसाव पेरियापालयम के पास कन्निगाइपैर स्थितसेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री में हुआ। जिसमें सात महिलाओं की मौत हो गई और 67 श्रमिक बीमार हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही अरक्कोनम स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चौथी बटालियन को अलर्ट किया गया। इसके बाद चेन्नई से 30 एनडीआरएफ कर्मियों की एक विशेष टीम तुरंत मौके के लिए रवाना की गई।

67 श्रमिक बेहोश, नौ गंभीर चेन्नई रेफर

तिरुवल्लूर जिले की कलेक्टर एस. कविता ने बताया कि 46 मरीजों का इलाज वेल्स हॉस्पिटल में और 21 का इलाज वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में चल रहा है। सबसे गंभीर रूप से बीमार नौ मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह घटना पेरियापालयम के पास मंजंगराई स्थित एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई में हुई। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही प्रभावित श्रमिकों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस बीच, शुरुआती दौर में कुछ लोगों की मौत की अफवाहें भी सामने आई थीं, लेकिन एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ने इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीज जीवित हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। डॉक्टर के अनुसार, अस्पताल में कुल 44 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें 43 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। इनमें से 15 से 16 मरीजों को इंट्यूबेट किया गया है, जबकि 11 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश प्रभावित कर्मचारी 24 से 25 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाएं हैं।

65 से अधिक श्रमिक बेहोश

सच छुपाने के लिए जांच में जानबूझकर देर कर रही है भाजपा - अखिलेश

नेशनल डेस्क । समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और कन्नौज से पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सच छुपाने के लिए अयोध्या के राम मंदिर में दिए गए दान और चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच में जानबूझकर विलंब कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज के एक दिन के दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राम मंदिर में हुए चढ़ावा घोटाले की जांच को भाजपा सरकार जानबूझकर लंबा खींच रही है, ताकि सच को छुपाया जा सके। उन्होंने कहा, एसआईटी जांच में देर की जा रही है ताकि सच सामने न आए। यादव ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में मामले की जांच पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि अधिकारी सुबूत मिटाने के लिए बेजा समय ले रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा, एसआईटी ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। फिर कहेंगे 15 दिन और इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह टिप्पणी तीन सदस्यीय विशेष जांच

दल (एसआईटी) द्वारा राम मंदिर में मिले चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोपों की जांच शुरू करने के कुछ दिनों बाद की है। एसआईटी रिकॉर्ड की जांच के साथ-साथ मंदिर के अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम की जनता अगले चुनावों में उसके मंत्रियों को हरा देगी। उन्होंने कहा, जब मंत्री और विधायक हारेंगे, तो मुख्यमंत्री भी नहीं बचेंगे। सपा अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर टिप्पणी करते हुए भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए योग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, लोगों को रोज योग करना चाहिए। भाजपा को योग सिर्फ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर याद आता है और वह इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।

ट्रंप ने दी फिर हमला करने की धमकी, भड़का ईरान; गालिबाफ बोले- बयानों को लेकर सावधान रहें

बर्गनस्टॉक । ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद एक बार फिर से टकराव के आसार नजर आने लगे हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामिक गणराज्य को धमकाने से कोई फायदा नहीं होगा।

गालिबाफ ने कहा, उन्हें अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाएं उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वे चाहे कुछ भी कहें, कार्रवाई हम करते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गालिबाफ ने कहा, क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता, तो वे आज इस तरह की निराशाजनक स्थिति में नहीं पहुंचते? हम अमेरिकी धमकियों को कोई महत्व नहीं देते। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने ईरान से लेबनान में अपने सहयोगी समूह हिजबुल्लाह को नियंत्रित करने और

इस्राइल पर हमले रोकने को कहा था। दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में वार्ता शुरू हुई थी। वार्ता शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनियों में से एक दी। उन्होंने लिखा, ईरान को तुरंत लेबनान में अपने सहयोगी समूहों को परेशानी पैदा करने से रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा हमला करेंगे, जैसा हमने पिछले सप्ताह किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्ती से।

ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त फोटो सेशन से बनाई दूरी

डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने नाराजगी जताते हुए अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रस्तावित संयुक्त फोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार, वार्ता शुरू होने से पहले दोनों

होर्मुज बंद किया तो नहीं बचेगा ईरान- ट्रंप की नई धमकी, कहा-अमेरिका खुद वसूलेगा टोल; तेल पर होगा कब्जा

पक्षों के बीच हाथ मिलाने और संयुक्त तस्वीर लेने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया।

ईरानी अधिकारियों ने आयोजकों को बताया कि वे ऐसे किसी भी मौके पर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यह अमेरिका का मीडिया शो है। गौरतलब है कि वार्ता के पहले ही दिन दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई। हालांकि, इसे रोकने के लिए आंतरिक तौर पर बातचीत करने का हवाला दिया गया है। इस बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने सरकारी मीडिया को बताया कि ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट देने संबंधी मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि रविवार की वार्ता में दुनिया भर के बैंकों में फंसी ईरानी संपत्तियों को मुक्त कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए इसे प्रमुख शर्तों में शामिल किया है। सूत्रों के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कतर के अधिकारियों के साथ इन धनराशियों को जारी करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की। वार्ता से पहले कतर ने लगभग छह अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां मुक्त करने की घोषणा की थी। हालांकि, ईरानी पक्ष ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य की वार्ताओं की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि लेबनान में इस्राइली हमले रुकते हैं या नहीं। प्रतिनिधिमंडल ने संकेत दिया कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रही है तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से पीछे हट सकता है, जो अमेरिका की प्रमुख मांगों में शामिल है।

हरियाणा में जमीन की अदला-बदली पर सख्ती, अब सरकार की मंजूरी के बिना नहीं होगा काम

चंडीगढ़ । शहरों और पालिकाओं के साथ लगते क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बजट सत्र में विधानसभा में विधेयक के पारित होने के बावजूद अभी तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिलने के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। जिस कारण वित्तायुक्त राजस्व और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम के तहत शहरों से लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कालोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए धारा 7-ए में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार एक एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अध्यादेश के जरिये संशोधित कानून को विगत 30 जनवरी से लागू किया गया है, जिसमें धारा 7-ए में «पट्टे» के बाद «या विनिमय विलेख» शब्द जोड़ा गया है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 अधिनियम संख्या 8) की धारा-7 में यह प्रविधान है कि किसी भी अधिसूचित शहरी क्षेत्र में, जो इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, एक एकड़ से कम क्षेत्रफल की किसी भी रिक्त भूमि का विक्रय, पट्टा या उपहार के रूप में अंतरण करने हेतु पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के पंजीकरण से पूर्व नगर एवं ग्राम नियोजन

निदेशक अथवा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि शहरी क्षेत्रों में अधिनियम की धारा-7(i) एवं (ii) का उल्लंघन करते हुए किए जा रहे अवैध कालोनियों के निर्माण को रोका जा सके। जमीन की रजिस्ट्रियों के दौरान पंजीकरण अधिकारियों ने पाया कि कई जगह छोटे भूखंडों की अदला-बदली करके अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान भूखंड लिए जा रहे थे। हालांकि ऐसे लेन-देन कानूनी रूप से एक्सचेंज कहलाते हैं, परंतु वास्तव में ये अप्रत्यक्ष विक्रय लेन-देन होते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा-7क के विनियामक प्रविधानों को दरकिनार किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1975 के अधिनियम संख्या-8 की धारा-7क में संशोधन कर अदला-बदली विनिमयन विलेख को भी उक्त प्रविधान के अंतर्गत लाया गया ताकि अवैध कालोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद-फरोख्त को हतोत्साहित किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बोले सीएम योगी

जहां योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न बीमारी

झांसी/लखनऊ।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और रोग, बीमारी तथा समय से पहले आने वाले बुढ़ापे से बचाव संभव है। झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई किले में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखकर जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति को शिक्षा, श्रम, कृषि, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योग को वैश्विक पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के लगभग 200 देश योग से जुड़ चुके हैं और इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग लोगों को बेहतर जीवन की दिशा दिखाती है।

इंटरनेशनल योग दिवस पर पधनमंत्री मोदी का मिशन योगा 365, कोलकाता से दिया बड़ा संदेश

कोलकाता ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कोलकाता के रेड रोड पर इंटरनेशनल योग दिवस के एक बड़े इवेंट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 21 जून अब दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव बन चुका है। पूरी दुनिया से योग को कमाल की तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और बंगाल से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि आज पूरी दुनिया योग के जरिए एक-दूसरे से कनेक्टेड फील कर रही है, और यही योग की असली ताकत है। योग सबको साथ लाता है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को योग दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां जो स्वच्छता से स्वागत की पहल शुरू की गई है, वह वाकई कमाल है। लोगों ने जिस तरह मिलकर सफाई की है, वह पूरे देश के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस पर बंगाल में होना बेहद खास है। यह वही पवित्र भूमि है जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत हुए और जहां से

निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को योग की ताकत से इंट्रोड्यूस कराया था। यहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने भी जन्म लिया। आज इस ऐतिहासिक धरती पर सबके साथ योग करना एक अलग ही लेवल का आध्यात्मिक अहसास दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि योग सिर्फ हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि यह मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। दुनिया के अच्छे फ्यूचर के लिए योग बेहद जरूरी है। आज का दिन हमें एक संकल्प लेने का मौका देता है कि योग को सिर्फ एक दिन का इवेंट न बनाएं, बल्कि इसे अपनी डेली लाइफ, अपने परिवार और आने वाली जनरेशन का हिस्सा बनाएं। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि इस साल योग 365 की एक नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत 100 दिनों का ऑनलाइन योग प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में 130 देशों के 30 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। आखिर में उन्होंने कहा कि जब हमारा समाज हेल्दी होगा, तभी देश भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने सबके सुखी और निरोगी रहने की कामना की।

अस्पताल से लेकर बाजारों तक कब्जा, दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण की मजबूत घेरेबंदी

पश्चिमी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद राहगीरों में एक नई उम्मीद जगी है। हालांकि, धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकारी एजेंसियों ने फुटपाथों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उनके रखरखाव और सुरक्षा को पूरी तरह से भुला दिया गया है। आज फुटपाथ या तो पूरी तरह टूट चुके हैं या फिर उन पर अवैध कब्जों का बोलबाला है। इस गंभीर समस्या को समझने के लिए पश्चिमी दिल्ली के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की वर्तमान दशा पर यदि विस्तृत नजर डालें तो जमीनी हकीकत फुटपाथ की देखरेख को लेकर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही को साफ साफ बयां करती है। अस्पताल जैसे संवेदनशील और आपातकालीन क्षेत्रों में मरीजों और तीमारदारों के लिए भी फुटपाथ किसी काम के नहीं हैं। यहां भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। क्षेत्र के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हरिनगर स्थित दीडीयू के आसपास के फुटपाथों पर दुकानदारों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। फुटपाथों का इस्तेमाल राहगीरों के चलने के लिए नहीं, बल्कि दुकानों के सामान को प्रदर्शित करने और उसे रखने के लिए किया जा रहा है। स्थिति केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, क्षेत्र के अधिकांश छोटे-बड़े निजी और सरकारी अस्पतालों के बाहर फुटपाथों का वजूद लगभग खत्म हो चुका है।जहां बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, वहां भी फुटपाथों का व्यवसायीकरण या निजीकरण कर दिया गया है। जनकपुरी डी-ब्लाक इलाके में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान एक साथ स्थित हैं। यहां फुटपाथों को बाकायदा घेर कर रखा गया है।

इन संस्थानों के सामने के फुटपाथों का उपयोग अब लोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए कर रहे हैं। कहीं-कहीं तो फुटपाथ को रोकने के लिए उन पर फूलों के गमले तक रख दिए गए हैं, जिससे छात्रों को मजबूरन मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है।

प्रमुख बाजार और चौक, फुटपाथ के दर्शन हुए दुर्लभ

व्यापारिक और रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर तो स्थिति और भी बदतर है। यहां पैदल चलने वालों के लिए रेंगना भी दूभर है। सागरपुर चौक से जनकपुरी मार्ग के बीच पूरे रास्ते में फुटपाथ पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है। रेहड़ी-पटरी वालों और दुकानदारों ने इसे अपनी सीमा मान लिया है। विकासपुरी, राजौरी गार्डन, मायापुरी, नजफगढ़ और द्वारका सेक्टर-7 (रामफल चौक) जैसे व्यस्ततम बाजारों में तो फुटपाथ के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। पूरे बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती।

कोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद

सरकारी एजेंसियों की घोर लापरवाही के कारण आज राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर मुख्य सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं।